भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **650**
उत्तर देने की तारीख **03** दिसम्बर**, 2025**

अमृतसर और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएनएल का पुनरुद्धार

650. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार बीएसएनएल को एक बार फिर से पंजाब में, विशेष रूप में अमृतसर जैसे सीमावर्ती जिलों में दूरसंचार की रीढ़ बनाना चाहती है, जहां खराब बुनियादी ढांचे, कमजोर रखरखाव, कर्मचारियों की कमी और फाइबर और डिश कनेक्टिविटी की कमी के कारण इसमें तेजी से कमी आ रही है, जबकि निजी ऑपरेटर दूरदराज और संवेदनशील क्षेत्रों में पूरी तरह से सेवा प्रदान करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पंजाब में बीएसएनएल के लिए कोई व्यापक पुनरुद्धार योजना बना रही है, जिसमें टॉवर बुनियादी ढांचे का उन्नयन, फाइबर कनेक्टिविटी में सुधार, स्थानीय रोजगार को बढ़ाना और सीमावर्ती गांवों में विश्वसनीय सेवाएं सुनिश्चित करना शामिल है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और कनेक्टिविटी दोनों महत्वपूर्ण हैं:

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का यह देखते हुए कि बीएसएनएल ऐतिहासिक पहुंच वाला एकमात्र ऑपरेटर है और ऐसे क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन, सुरक्षा संचार और आर्थिक कार्यकलाप को बहाल करने की क्षमता रखता है, सीमा क्षेत्रों में इसके पुनरुद्धार के लिए एक विशेष पैकेज का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (च) बीएसएनएल दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने के लिए अखिल भारत स्तर पर संस्थापना हेतु स्वदेशी रूप से विकसित एक लाख 4जी साइटों को रॉल आउट कर रहा है। दिनांक 15.11.2025 की स्थिति के अनुसार, कुल 97,208 साइट संस्थापित की गई हैं और 93,859 4जी साइट ऑन-एयर हैं। बीएसएनएल ने पंजाब में कुल 4,012 4जी बीटीएस संस्थापित किए हैं जिसमें सीमावर्ती ज़िलों में 903 4जी बीटीएस और अमृतसर में 291 4जी बीटीएस शामिल हैं। भारतनेट परियोजना के तहत दिनांक 17.11.2025 की स्थिति के अनुसार पंजाब की कुल 12,668 ग्राम पंचायतों (जीपी) को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी (ओएफसी) से जोड़ा जा चुका है।

इसके अलावा, मांग के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों और गांवों के लिए फाइबर का विस्तार करने हेतु 1.39 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 04.08.2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को अनुमोदन दिया गया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 करोड़ हाई स्पीड एफटीटीएच ब्रॉडबैंड कनेक्शनों का प्रावधान भी शामिल है। बीएसएनएल इस स्कीम के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी है।

सरकार सीमावर्ती और दूर-दराज के क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज को और बढ़ाने के लिए 4जी सेचुरेशन स्कीम, बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)/बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट (बीआईपी) आदि जैसी विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। इन स्कीमों का विवरण https://usof.gov.in पर उपलब्ध है।

*****